(c) what criteria the Ministry has followed in selecting the workers representatives on both the Boards?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. "A. SANGMA): la) to (c) Yes, Sir; the secretariat of the Wage Boards has been doing preparatory work since their constitution. A meeting of the Wage Boards has also been convened on 3-4-1995. Workers representatives on both the Boards have been selected on the basis of the recommondations of the Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees Organisations.

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी

*91. श्री ईश दत्त यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक प्रतिष्ठानों में मजदूरों को न्यूनतम एवं निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है अथवा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया है अथवा ऐसा करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने नियमों का उल्लघंन करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन के लिये समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । सरकार ने 29-30 सितम्बर, 1994 को भुवनेश्वर में पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, 4 अक्तूबर, 1994 को त्रिवेन्द्रम में दक्षिणी क्षेत्र और 25 अक्तूबर, 1994 को जयपुर में मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित किये हैं । इन सम्मेलनों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्त्तन को सुदृढ़ बनाने के लिये अनेक निर्णय लिये गये हैं । इनमें प्रिंट मीडिया, रेडियो प्रसारण, इलैक्ट्रानिक मीडिया, होर्डिंग आदि के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रसार, अधिनियम के उल्लंघन के लिये शास्ति में बढ़ोतरी, दावा प्राधिकारियों की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदंड का प्रसार, दावा निपटान पद्धतियों को सरल बनाना आदि शामिल है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्य सहयोगी विभागों की सहायता लेकर, निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि कर के, और जिला स्तरीय निगरानी समितियां आदि गठित करके प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किये जाने की भी सलाह दी गयी है ।

Production of rubber

*92. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total production of rubber during the last three years in the country, state-wise;

(b) the total requirement of rubber during the currnt year in the country, industry-wise;

(c) whether the Government have any proposal to import natural rubber during the current year; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The total *pro-*

tion of rubber during last three years in the country, Statewise, is as under:

	Production (Tonnes)		
	1991-92	1992-93	1993-94
Kerala	343,109	368.648	408,311
Tamil Nadu	13,975	14,250	14,720
Karnataka	7,260	7,910	6,626
Tripura	1,600	1,740	2,351
A & N Islands	485	515	539
Others	316	427	613
TOTAL :	366,745	393,490	435,160

(b) The total requirement of rubber during the current year in the country, industry-wise, is as under :

	1994-95 (Estimated) (Tonnes)
Automotive tyres & tubes	213,000
Cycle tyres & tubes	67,300
Camel back	31,500
Footwears	50,800
Belts & hoses	33,600
Latex foam	27,400
Cables & wires	1,400
Battery boxes	1,500
Dipped goods	24,300
Others	32,100
TOTAL :	483,000

(c) and (d) Yes, Sir. The Government has allowed import of 10,000 MTs of natural robber at nil duty in other to bridge the gap between demand and supply, besides permitting the import of rubber at normal duty against special import licences granted to Export Houses, Trading Houses, etc.

High prices of pulses add edible olls

*93. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES. CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that prices of pulses and edible oils in the country are very high and this is causing great hardship to weaker sections of society;

(b) whether Government propose to include these items in Public Distribution System;

(c) if so, the details of the proposal; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) The prices of pulses and edible oils are rising due to the gap between demand for and supply of these items. To augment their supplies in the market and containing their prices, in addition to taking measures for increasing their domestic production, these commodities have been placed under Open General Licence for imports. To mitigate the hardships of the poor, imported palmolein is being supplied through fair price shops under the Public Distribution System and cooperative stores at a price lower than the open market price. Pulses are also being supplied through the retail outlets of cooperative stores, Kendriya Bhandars and the State Supplies Corporations although this is not an item under the Public Distribution System.

(b) to (d) Imported edible Palmolein is already being allocated to States/UT. Governments by the Central Government for distribution through the PDS. These allocations are made to the States/UTs. subject to availability of stocks and demands received from them from time to time. During the year 1994-95, about 1.08 lakhs tonnes of RBD Palmolein was imported for distribution through the PDS and the same is expected to be distributed by the end of the current financial year.

In respect of pulses, however, in view of wide variations in consumer preferences for different varieties of pulses in different region of the country and the existing pattern of production, it is fell that contralined procurement of pulses by the Central Government agencies may not be feasible.

बीड़ी मजदूरों का कल्याण

*94. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बीड़ी मजदूरों की वर्तमान संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1984 और 1990 में बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ग) क्या श्रम मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो देशभर के मजदूरों के कल्याण के लिए इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिए हैं; और

(ङ) सरकार उन पर क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० एस० संगमा) (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में बीड़ी कर्मकारों की